



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 3 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2001/पौष 13, 1922

No. 3]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2001/PAUSA 13, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2001

सं. टीएएमपी/4/98-विधिध.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार महापत्तन न्यासों द्वारा बिल बनाने के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग के प्रशुल्क का भारतीय रुपए में परिवर्तन करने से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करता है।

अनुसूची

सं. टीएएमपी/4/98-विधिध

**आदेश**

(नवम्बर, 2000 के 27वें दिन पारित किया गया)

यह मामला पत्तनों द्वारा बिल बनाने के समय अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग के प्रशुल्कों को भारतीय रुपयों में परिवर्तन करने के कुछ मुद्दों से संबंधित है। प्राधिकरण द्वारा देखा गया है कि इस उद्देश्य के लिए अपनाई जाने वाली विनिमय दर के विषय में पत्तनों द्वारा एकसमान पद्धति नहीं अपनाई जा रही है। पत्तन प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को विनिमय दर को 'सीमा-शुल्क दर' के साथ संबद्ध करने का सुझाव दिया जाता है क्योंकि यह एक सर्वमान्य पद्धति है।

2. विशाखापट्टणम पत्तन न्यास द्वारा जलयान संबंधी प्रभार वसूलने से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणी के संदर्भ में जहाज़रानी मंत्रालय (एमओएस) ने भी यह मुद्दा हमारे विचार-विमर्श के लिए उठाया था। जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामले में, अगस्त 1996 में बर्थ में रखी गई और 3 वर्षों से अधिक समय तक पत्तन में मौजूद रही प्लवमान क्रेन के मामले में विशाखापट्टणम पत्तन न्यास प्लवमान क्रेन के पहुंचने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार बर्थ किराया प्रभार बराबर वसूल कर रहा था। इसका कारण पिछला सरकारी अनुदेश है जिसमें यह विनिर्दिष्ट था कि

जलयान के पहुंचने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर अपनाई जानी चाहिए। जहाजरानी मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि सभी महापत्तनों को दिन-प्रतिदिन आधार पर प्रचलित विनिमय-दर के अनुसार बर्थ किराया प्रभार वसूल करने की सलाह दी जाए।

3. सभी महापत्तन न्यासों से विनिमय सीमा-शुल्क दर अथवा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की प्रतिदिन की दरें और जलयान के पहुंचने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर वसूल करने की वर्तमान पद्धति के स्थान पर प्रभारों के प्रभावी होने के समय उचित विनिमय दर लागू करने की पद्धति को अपनाने के बारे में उनके विचार जानने के लिए मंत्रणा की गई। विनिमय सीमा-शुल्क दर लागू करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाईयों के बारे में वित्त मंत्रालय से भी मंत्रणा की गई।

4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने सूचित किया है कि अधिसूचित विनिमय सीमा-शुल्क दरों को लागू करने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई है। बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि इन दरोंको अधिसूचित करने की शक्तियाँ सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित है और ये उपबन्ध सीमा-शुल्क मूल्यों के बारे में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ हुए करारों के अनुरूप हैं।

5. सभी महापत्तनों ने उन्हें भेजे गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियाँ दे दी हैं। इन पत्तन न्यासों से प्राप्त टिप्पणियों से प्रकट होता है कि अधिकांश पत्तन न्यासों ने जलयान के पहुंचने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक की दरें प्रयोग करने की प्रचलित पद्धति जारी रखने को वरीयता दी है।

6. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र सम्पूर्ण जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं :

- (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को अधिसूचित विनिमय सीमा-शुल्क दरों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सीमा-शुल्क दर को अपनाने में ऐसी कोई विधिक रूकावट नहीं है जिसकी आशंका व्यक्त की गई थी।
  - (ii) महापत्तनों में विनिमय दर लागू करने के बारे में एकसमान पद्धति नहीं अपनाई गई है जबकि प्रयोक्ता समान मार्ग अपनाना चाहते हैं।
  - (iii) एमबीपीटी, सीओपीटी, वीपीटी और टीपीटी अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग के प्रशुल्कों के परिवर्तन के लिए सीमा-शुल्क दर अपनाने के पक्ष में हैं। परन्तु केपीटी, जेएनपीटी, एमओपीटी, पीपीटी, एनएमपीटी और सीपीटी भारतीय रिजर्व बैंक की दैनिक विनिमय दर के प्रयोग को वरीयता देते हैं, जबकि सीएचपीटी भारतीय स्टेट बैंक की दर के प्रयोग को वरीयता देता है। इन पत्तनों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की दर प्रयोग करने के बारे में यह तर्क दिया गया है कि उन्हें इस पद्धति से कोई कठिनाई नहीं हो रही है और यह पद्धति निर्विघ्न रूप से कार्य कर रही है। इन सभी पत्तनों ने राय व्यक्त की है कि पद्धति में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पिछले काफी समय से निर्विघ्न रूप से चल रही है।
  - (iv) जेएनपीटी को छोड़कर सभी पत्तनों का मत है कि अमेरिकी डॉलर मूल्य-वर्ग के पत्तन प्रशुल्क के परिवर्तन के लिए जलयान के पहुंचने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को लागू किया जा सकता है। इन पत्तनों ने संबंधित सेवा के समय प्रचलित विनिमय दर को अपनाने में कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों का उल्लेख किया है। भिन्न-भिन्न समय पर जलयानों के आवागमन के लिए पाइलट प्रभार वसूल किया जाता है, परन्तु प्रशुल्क एकमुश्त प्रभार है। इसी प्रकार, यदि भिन्न-भिन्न सेवा के समय भिन्न-भिन्न विनिमय दरें लागू की जाती हैं तो 8 घंटे के आधार पर बर्थ किराया का बिल बनाने में कठिनाई आ सकती है। जेएनपीटी ने संबंधित सेवा के समय एक उपयुक्त विनिमय दर का निम्नलिखित सुझाव दिया है :
- (क) जलयान के प्रस्थान की तारीख को प्रचलित विनिमय दर की गणना सभी जलयान संबंधी प्रभारों के लिए की जाएगी।
  - (ख) आयात कंटेनरों की सुपुर्दगी की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार विनिमय दर।
  - (ग) निर्यात कंटेनरों की लदाई की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार विनिमय दर।

- (v) जहाजरानी मंत्रालय द्वारा उल्लिखित वीपीटी मामले को ध्यान में रखते हुए जलयान के पहुंचने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर आधारित बिल बनाने की वर्तमान पद्धति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जहाजों को पत्तन में लम्बी अवधि तक खड़े करने के मामलों में विनिमय दर की आवधिक समीक्षा करना अपेक्षित है। यदि ऐसी समीक्षा जहाजों के पहुंचने की तारीख से 30 दिनों में एक बार की जाए तो उपयुक्त होगी। उल्लेखनीय है कि विनिमय की सीमा-शुल्क दर भी सामान्यतः कलेण्डर माह में एक बार संशोधित की जाती है।
7. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तर्कों और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित निर्णय करता है :
- (i) पत्तनों के सुझावों को ध्यान में रखकर, बिल बनाने के समय डॉलर मूल्य-वर्ग के प्रशुल्को का भारतीय रुपए में परिवर्तन करने के उद्देश्य से आरबीआई की दैनिक दर लागू करने की वर्तमान पद्धति चालू रहेंगी।
  - (ii) संबंधित सेवा के समय विनिमय दरों को अपनाने में व्यावहारिक कठिनाईयों पर विचार करके, जलयान के पहुंचने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर आधारित बिल बनाने की वर्तमान पद्धति चालू रखने की अनुमति दी जाती है।
  - (iii) 30 दिन से अधिक जलयानों को पत्तन में खड़ा करने के मामलों में जलयान के पहुंचने की तारीख से 30 दिन में एक बार विनिमय दर की नियमित समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में समीक्षा के समय प्रचलित उपर्युक्त विनिमय दर के अनुसार बिल बनाने के आधार में साफ़ परिवर्तन होगा।
8. सभी महापत्तन न्यासों को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे तदनुसार अपनी दरों के मान में उपयुक्त परिवर्तन करें।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/2000(असा.)]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2001

**No. TAMP/4/98-Misc.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby clarifies the issues relating to re-conversion of US dollar denominated tariff into Indian Rupee at the time of billing by the Major Port Trusts as in the Order appended hereto.

### SCHEDULE

**No. TAMP/4/98-Misc.**

### **ORDER**

(Passed on this 27th day of November 2000)

This case relates to some issues about re-conversion of US dollar denominated tariffs to Indian rupees at the time of billing by the Ports. This Authority has noted that no uniform practice is being followed by the Ports with regard to the rate of exchange to be applied for the purpose. Port users / representative bodies of port users have been suggesting to link the exchange rate with the 'Customs Rate', as it is a well established system.

2. The Ministry of Shipping (MOS) has also raised this issue for our consideration in the context of an audit observation relating to levy of vessel-related charges by the Visakhapatnam Port Trust. In the case referred by the MOS, the berth hire charges in respect of a floating crane that berthed in August 1996 and remained in the port for over 3 years was continued to be collected by the VPT at the exchange rate prevailing on the day of arrival of the floating crane. This was because of a stipulation in the earlier Government Instruction that the exchange rate prevailing on the date of arrival of vessel should be considered. The Ministry of Shipping has suggested that all Major Ports may be advised to collect berth hire charges as per the exchange rate prevailing on a day-to-day basis.

3. All the Major Port Trusts have been consulted to ascertain their views on adoption of the Customs Rate of exchange or RBI daily rates and applying the appropriate exchange rate at the time of incidence of charges instead of the existing practice of going by the exchange rate prevailing on the date of arrival of the vessel. The Ministry of Finance has also been consulted about any difficulties faced in operation of the Customs Rate of exchange.

4. The Central Board of Excise and Customs (CBEC) has intimated that it has not faced any difficulty in the operation of Customs notified rates of exchange. It has also informed that the powers to notify these rates have been laid down in Section 14 of the Customs Act and these provisions are also consistent with the World Trade Organisation (WTO) Agreements on Customs Value.

5. All the Major Ports have furnished their comments on the issues referred to them. Comments received from the Port Trusts reveal that a majority of Port Trusts prefer to continue with the prevailing system of using the RBI rates on the date of arrival of the vessel.

6. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following points have emerged:

- (i). **The CBEC does not face any difficulty in the operation of the Customs notified rates of exchange.** This indicates that there is no legal hassle in the adoption of the Customs Rate as apprehended in some quarters.
- (ii). There is no uniform practice followed at the major ports with regard to the rate of exchange to be applied. The users want a uniform approach.
- (iii). The MBPT, COPT, VPT, and TPT are in favour of adopting the Custom Rate for conversion of the US dollar denominated tariffs. However, the KPT, JNPT, MOPT, PPT, NMPT and CPT prefer to use the RBI daily exchange rate, while the CHPT prefers to use the SBI rate. The reason given for using the RBI rate by these ports is that they have not faced any difficulties in this system and it is functioning smoothly. All these ports have opined that there is no need to change a system that has been operating smoothly for quite some time.
- (iv). All the Ports except the JNPT are of the opinion that the exchange rate prevailing on the date of arrival of the vessel may be taken for application for conversion of the US dollar denominated port tariff. These ports have pointed out some of the practical problems of adopting the exchange rate prevailing at the time of incidence of service. Pilotage charges collected are for both inward and outward movement, which take place at two different points of time; but, the tariff is a consolidated charge. Likewise, billing of berth hire on 8 hourly basis may pose problems if different exchange rates at the incidence of service are to be applied.

The JNPT has suggested an appropriate exchange rate at the time of incidence subject to the following:

- (a) Exchange rate as prevailing on the date of departure of the vessel may be reckoned for all vessel related charges.
- (b) Exchange rate as on the date of delivery for import containers.
- (c) Exchange rate as on the date of shipment for export containers

- (v). The existing system of billing based on the exchange rate prevailing on the date of arrival of the vessel can not be allowed to continue in the light of the VPT case brought out by the Ministry of Shipping. The exchange rate requires periodic review in the cases of ships staying in a port for a longer period. Such a review, if made once in 30 days from the date of arrival of ships, appears to be reasonable. It is noteworthy that the Customs Rate of exchange is also generally revised once in a calendar month.

7. In the result and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority hereby decides as follows:

- (i). Bearing in mind the suggestions of the Ports, the existing practice of applying the RBI daily rate shall continue for the purpose of conversion to Indian rupees of dollar denominated tariffs at the time of billing.
- (ii). Considering the practical problems of adopting the exchange rates at the time of incidence of service, the existing system of billing based on the exchange rate prevailing on the date of arrival of the vessel is allowed to be continued.
- (iii). A regular review of the exchange rate shall be made once in thirty days from the date of arrival of the vessel in cases of vessels staying in the port for more than thirty days. In such cases, the basis of billing shall change prospectively with reference to the appropriate exchange rate prevailing at the time of the review.

8. All the Major Port Trusts are hereby directed to introduce appropriate changes in their Scale of Rates accordingly.

S. SATHYAM, Chairman

[No. ADVT./III/IV/143/2000(Exty)]

29/12/2001-2

